सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष: 30 अंक: 1-2 22 जनवरी से 5 फरवरी, 2015 मुख्य संपादक - कॉ. कृष्ण चक्रवर्ती E-mail :sarvaharadrishtikon@gmail.com मूल्य: 2 रुपये

देश भर में मनाया गया साम्प्रदायिकता विरोधी एवं सद्भावना दिवस

दिल्ली: 6 दिसम्बर 2015, सीपीआई, सीपीआई(एम), एसयूसीआई(कम्युनिस्ट), सीपीआई(एमएल) लिबरेशन, आरएसपी और फारवर्ड ब्लॉक 6 वामपंथी पार्टियों द्वारा आहूत अखिल भारतीय साम्प्रदायिकता विरोधी-दिवस पर दिल्ली में मण्डी हाऊस से संसद मार्ग तक एक जुलूस निकाला गया। जुलूस की अगुआई कर रहे नेताओं में एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड सत्यवान और दिल्ली राज्य सांगठनिक कमेटी सदस्य कॉमरेड रमेश शर्मा शामिल थे। संसद मार्ग पर हुई विरोध सभा को एसयूसीआई(सी) के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती के अलावा सीपीआई(एम) के कॉमरेड सीताराम येचुरी, सीपीआई के कॉमरेड डी. राजा, फारवर्ड ब्लाक के कॉमरेड देवराजन, सीपीआई (एमएल) लिबरेशन की कॉमरेड कविता कृष्णन व अन्य नेताओं ने सम्बोधित किया। कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती का संक्षिप्त भाषण यहाँ दिया जा रहा है।

साथी सभापति मंच पर बैठे बिरादराना पार्टियो के नेतागण साथियो, एवं दोस्तो,

हम 6 दिसम्बर को एक काला दिवस के रूप में मानते हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। भारत की

(शेष पृष्ठ 2 पर)

शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण के खिलाफ आन्दोलन

शिक्षा विरोधियों नीतियों के खिलाफ 'ऑल इण्डिया सेव एजुकेशन' ने किया राष्ट्रीय आन्दोलन

केन्द्र सरकार की जनविरोधी शिक्षा नीतियों, विशेषकर देश की स्कूली शिक्षा को तबाही और गर्त में धकेल देने वाली 'बेरोकटोक पास करने की नीति' (छव क्मजमदजपवद च्वसपबल) के खिलाफ आज 23 नवम्बर, 2015 को देश भर से आये हजारों शिक्षाप्रेमी लोगों द्वारा संसद पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

यह विरोध प्रदर्शन शिक्षा पाने के लोगों के अधिकार पर केन्द्र सरकार द्वारा निरंतर किये जा रहे हमलों के खिलाफ जमीनी स्तर तक लोगों को संगठित करने के उद्देश्य से ऑल इण्डिया सेव एज्युकेशन कमेटी(एआईएसईसी) द्वारा छेड़े गये देशव्यापी अभियान के समापन के तौर पर किया जा रहा है। शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण की नीतियों के चलते स्कूलों के साथ-साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भी बेतहाशा फीस बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा को सर्विस के रूप में मानना और इसे डब्ल्यूटीओ और जीएटीएस के तहत लाने का प्रयास अंततः शिक्षा को इसके मानव निर्माण और चरित्र निर्माण के सारतत्व से विहीन कर देगा। पूरी शिक्षा व्यवस्था के भगवाकरण के केन्द्र सरकार के प्रयासों ने भारतीय नवजागरण के पुरोधाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया है जिन्होंने आजाद भारत में वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी शैक्षिणक ढांचा लागू करने का ख्वाब देखा था।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

बुद्धिजीवियों-लेखकों-वैज्ञानिकों एवं मिस्टर आमिर खान साम्प्रदायिक हमलों का विरोध करें

एसयूसीआई(सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 27 नवम्बर को निम्नलिखित बयान जारी किया:

कोई भी संवेदनशील और जनवादी सोच रखने वाला व्यक्ति निश्चित ही इस तथ्य को स्वीकार करेगा कि जबरन पुनःधर्मपरिवर्तन से शुरू कर चर्चों पर बार-बार के हमलों और साम्प्रदायिक दंगों, हाल ही में गोमांस की अफवाह पर पीट-पीट कर मार देने की घटना तथा विख्या तर्कशास्त्रियों की हत्याओं की एक के बाद एक घटने वाल घटनाओं ने एक ऐसी स्थिति और वातावरण पैदा कर दिया जिसके चलते तमाम अल्पसंख्यक समुदाय भयभीत हो गए हैं। इस बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ प्रतिष्ठित लेखकों, कलाकारों या प्रख्यात वैज्ञानिकों ने भी जोरदार प्रतिवाद किया और देश की बहुत सी नामी-गिरामी हस्तियों ने प्रतिवाद स्वरूप अपने पुरस्कार भी लौटा दिए हैं। जहाँ केन्द्र सरकार के लिए जरूरी था कि वह इस प्रकार की साम्प्रदायिक गतिविधियों के खिलाफ कठोर एवं तत्काल कार्रवाई करती। वहीं चुप रह कर केन्द्रीय सरकार ने संघ परिवार तथा शिव सेना के सदस्यों को इन जानी मानी हस्तियों को राष्ट्र विरोधी करार देते हुए उन पर हमले जारी रखने की असल में इजाजत दे दी और स्थिति को इस तरह और भी बदतर बना दिया। केन्द्र सरकार की परोक्ष मदद से पैदा हुई यह स्थिति निश्चित ही अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा करेगी, असल में इसी के चलते मिस्टर आमिर खान ने अल्पसंख्यकों की इस भावना को व्यक्त किया था। मि. खान के वक्तव्य से स्थिति की गंभीरता का अहसास करने की बजाए केन्द्र सरकार ने चुप रह कर हिन्दू कट्टरपंथियों को इजाजत दे दी। मि. खान पर जुबानी हमला बोलने की और इस तरह स्थिति को और भी बिगाड़ने में मदद दी। ये हिन्दू कट्टरपंथी मि. खान पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके वक्तव्य ने दुनिया के सामने भारत की छवि खराब की है। लेकिन सच्चाई इसके बिलकुल विपरीत है। असल में हिन्दू कट्टरपंथियों द्वारा बार-बार किए जा रहे साम्प्रदायिक कुकृत्यों की वजह से ही वस्तुतः भारत की छवि खराब हुई है। और इसी के चलते देश का जनवादी माहौल दूषित हुआ है। जिसे छिपाने का प्रयास ये लोग कर रहे है। मिस्टर खान के वक्तव्य पर ही हल्ला मचा कर।

हिन्दू कट्टरपंथियों के साम्प्रदायिक कुकृत्यों और घोर साम्प्रदायिकता से प्रेरित जुबनी हमले जो इनके द्वारा बुद्धिजीवियों, लेखकों, वैज्ञानिकों के साथ-साथ मि. आमिर खान पर किए जा रहे हैं हम इन दोनों का ही विरोध करते हैं और केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि वह इन साम्प्रदायिक गतिविधियों पर सख्ती से और तुरन्त रोक लगाए और हिन्दू कट्टरपंथियों के प्रचार पर लगाम लगाए और सभी अल्पसंख्यकों के लिए सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करें।

हम लोगों का आह्वान करते हैं कि वे मजबूती के साथ एकजुट रहें और दृढ़तापूर्वक बढ़ते हुए साम्प्रदायिक और फासीवादी माहौल का मुकाबला करें।

देश भर में सद्भावना दिसवस..

(पृष्ठ 1 का शेष)

आजादी के बाद ऐसी चुड़ांत जनवाद विरोधी घटना कभी भी नहीं घटी थी। उस समय जो भयंकर साम्प्रदायिक स्थिति पैदा हुई थी, आज की स्थिति एक हिसाब में उसमें भी अधिक गंभीर है।

आज किन परिस्थियों में हम इस सभा में शामिल हुए हैं वो आप सभी जानते है। हमारे समाज में आजादी के बाद से ही साम्प्रदायिक दंगे होते रहे है। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति तैयार हुई है, ये सिर्फ साम्प्रदायिक स्थिति है ऐसा ही नहीं ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें संघ परिवार या शिवसेना के बारे में आलोचना करना ही मुश्किल हो गया है। आप यदि करेंगे तो साथ ही साथ आप पर हमला किया जाएगा। जनवाद की जो मामूली चीज होती है, वो है राजनैतिक पार्टियों, राजनैतिक लाईन को विषय में चर्चा बहस करती है। उन्हें अपनी आपसी राजनैतिक लाइन की व्याख्या करना या विचार रखने का पूरा हक रहता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, उनकी लाइनकी आलोचना करना असंभव हो गया है। मतलब उनकी लाइन को ही आपको मानना पडेगा नहीं तो आपको देशद्रोही बना दिया जाएगा नहीं तो आप पर हमला किया जाएगा। और फिर ये लोग जनवाद की भी बात करते हैं ये कौन सा जनवाद है।

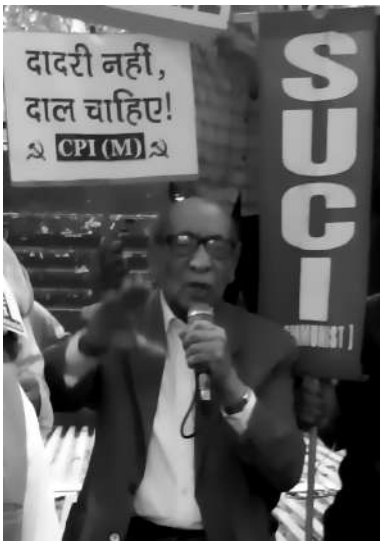

आप यदि खयाल करके देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा के सत्ता में लाने के साथ-साथ एक भयंकर परिस्थति तैयार होने लगी है। घर वापसी या जबरदस्ती पुनर्धर्मपरिवर्तन शुरू हो गया। सिर्फ मुसलमान को ही नहीं इसाई को भी जबरदस्ती हिन्दू बनाने का आन्दोलन शुरू हा गया। यदि ये मान भी लिया जाए कि बादशाह सुलतानों के जमाने में हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था या ब्रिटिश राज में हिन्दुओं को जबरदस्ती इसाई बनाया गया था तो भी उन लोगों की चौथी पांचवीं पीढ़ी के जो लोग हैं वो तो परिवर्तित नहीं हुए, उन्होंने तो मुसलमान या इसाई होकर ही जन्म लिया है। उनको जो आज आप जबरदस्ती परिवर्तित कर रहे हो, ये तो सामंती आचरण से अलग कहा है? ये भी तो सामंती आचरण ही है। ये जनवाद कहाँ है? आप तो जनवाद की बात करते हो। इतना ही नहीं पिछली विधान सभा चुनाव से लोक सभा चुनाव से कुछ दिन पहले मुज्जफ्फरनगर में दंगा हुआ, जिसका फायदा चुनाव में लिया गया, फिर पिछली विधान सभा चुनावों से पहल 6-6 बार चर्च पर हमला हुआ। इन सब घटनाओं से धरे-धीरे एक साम्प्रदायिक माहौल तैयार होने लगा। इसी क्रम में दादरी में गौमांस खाने का बहाना बना कर मोहम्मद अखलाक को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन नृशंसता की एकमात्र मिसाल नहीं है, इसके कुछ दिन बाद ही ऐसे ही गौमांस खाने का बहाना बनाकर हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति को जान से मार दिया गया। सिर्फ मुसलमान या इसाई पर ही हमला हुआ ऐसा नहीं, श्री पनसरे, श्री, धबोलकर एवं श्री कलबुर्गी जो जान माने लेखक एवं समाजसेवी थे उनकों भी जान से मार दिया गया। उनका अपराध क्या था? अपराध सिर्फ यही था कि वो तर्कवादी थे। इन सभी घटनाओं से ऐसी परिस्थिति सष्टि हुई है कि सभी जनवादी ताकतों के मन में आ रहा है कि देश मं जनवाद का क्या होगा? बहुत नामी लेखक, कलाकार, साहित्यकार, इतिहासकार, यहाँ तक कि नामी वैज्ञानिक इसका विरोध करने पर मजबूर हो गए। और उन्होंने प्रतिवाद स्वरूप अपने पुरस्कार वापस कर दिए। ऐसी घटना भारत के जनवादी आन्दोलन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। ये एक एतिहासिक घटना है। इससे भी पता चलता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। जानेमाने बुद्धिजीवियों की शंका है कि कही देश में फासीवाद न आ जाए। दुखिया के जिन-जिन देशों में फासीवाद आया इसी रास्ते से ही आया। असहिष्णुताका मनोभाव यदि शासक पार्टियों की तरफ से होता है। बेशक सीधा पार्टी की तरफ से न हो उस को दे ही विभिन्न संगठनों को तरफ से भी हो तो भी परिवेश ऐसा ही भयंकर हो जाता है। सबसे खतरनाक होता है कट्टरपंथी मनोभाव, जो अंधेपन से आता है। अंधेपन वाली मानसिकता खासकर धर्मांध ता जितनी बढ़ती जाती है। उतना ही कट्टरपंथी मनोभाव बढ़ता जाता है। और ये आ रहा है साम्प्रदायिक मानसिकता से। इसलिए देश के अल्पसंख्यकों के मन में शंका पैदा हो रही है। ये तो स्वभाविक ही है। और आमिर खान ने अपनी बातों में इसी का इशारा किया है। जहाँ सरकार को स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए था वहाँ उन पर ही झूठा आरोप लगाया गया और कहा गया उन्होंने दुनिया की नजर में देश की छवि खराब की है। लेकिन वास्तव है कि हिन्दू कट्टरपंथियों के आचरण से ही दुनिया की नजर में देश की छवि खराब हो रही है। सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए जब कदम उठाने की आवश्यकता थी तथा जब जनवाद की रक्षा करने की जरूरत थी वहाँ पर सरकार की तरफ से वास्तव में इनको प्रोत्साहित ही किया गया। गृहमंत्री ने कहा कि सेक्युलरिज़्म का मतलब धर्मनिरपेक्षता नहीं ये पंथ निरपेक्षता होता है। धर्म के अन्दर ही जो विभिन्न ग्रुप होते हैं इनको ही पंथ कहा जाता है। उनके कहने का मतलब ही हुआ कि राजनीति में शिक्षा के क्षेत्र में अथवा जन-जीवन में धर्म की भूमिका रहेगी। इतिहास के छात्र जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का जन्म यूरोप के नवजागरण काल में हुआ एवं पूँजीवाद के विकास के युग मं और पूँजीवाद पुराना सामंती समाज को मूलत: धर्म पर आध ारित था उसको मुकाबला करके आया। सामंती व्यवस्था जिसमें राजा को इश्वर का प्रतिनीधि के रूप में माना जाता था उस व्यवस्था को उखाड़कर जनवादी संसदीय व्यवस्था को लाया गया। सेक्युलर राजसत्ता न तो धर्म को प्रोत्साहित करती है और न ही उसमें हस्तक्षेप करती है। राजसत्ता धर्म को एक व्यक्तिगत मामला मानती है जिसके साथ राजसत्ता का कोई संबंध नहीं है। एवं ध र्मनिरपेक्ष जनवादी समाज में धर्म में विश्वास करने और धर्म को न मानने वाले, दोनों को ही समाजन दृष्टि से देखा जाता है। परिणामस्वरूप सेक्युलरज़्म का अर्थ ध र्मनिरपेक्षता बिना और कुछ नहीं हो सकता है गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सेक्युलरिज़्म की धारणा का जन्म यूरोप में हुआ इसलिए भारत की परिस्थिति में ये धारणा

(शेष पृष्ठ 5 पर)

ए.आई.डी.एस.ओ. ने नेरोबी में डब्ल्यू.टी.ओ.-गैट्स के खिलाफ अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस मनाया गया

एआईडीएसओ की अखिल भारतीय कमेटी की ओर से 12 दिसम्बर 2015 को अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस मनाने के आह्वान पर एआईडीएसओ की दिल्ली राज्य कमिटी ने नाइरोबी में होने वाली विश्व व्यापार संगठन की बैठक जो कि शिक्षा को गैट्स के अंतर्गत लाने की दृष्टि से हो रही है तथा आन्दोलनकारी छात्रों पर पुलिस के बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। दिल्ली के विभिन्न संस्थानों से छात्र इकट्ठा हुए तथा शिक्षा को वैश्विक बनाने, शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण, जनवादी आन्दोलन में पुलिस हस्तक्षेप के खिलाफ तथा भारत सरकार को विश्व व्यापार संगठन से बाहर आने की मांग को लेकर नारेबाजी की। विश्व व्यापार संगठन के उच्च शिक्षा को गैट्स के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव वाले दस्तावेज की परीकृति को जलाया गया। उसी समय एक सभा का आयोजन किया गया। जिसे एआईडीएसओ के दिल्ली राज्य अध्यक्ष भास्करानन्द, सचिव प्रशांत कुमार, राज्य कमेटी सदस्य तथा विभिन्न संस्थानों से आए छात्र प्रतिनिधियों ने सम्बोधित किया। सभा का संचालन एआईडीएसओ के दिल्ली राज्य कमेटी सदस्य राहुल सरकार ने किया।

वक्ताओं ने बताया कि भारत सरकार शिक्षा के फण्ड की जिम्मेदारी से निर्लज्जतापूर्वक भाग रही है। शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियाँ लागू हो रही है। वैश्विकरण के तहत शिक्षा में तीव्र परिवर्तन हो रहे है। विभिन्न देशों के निवेशक शिक्षा को लाभप्रद निवेश के रूप में देख रहे हैं। वैश्विक व्यापार को शिक्षा में लाने के लिए विभिन्न सरकारें शिक्षा को वैश्विक, उत्पाद बनाने के लिए उठ खड़ी हुई हैं। यह सभी प्रयास पूँजीवाद-साम्राज्यवाद को बढ़ते संकट से बचाने के लिए किए जा रहे हैं। शिक्षा गैट्स के अंतर्गत आने के बाद यह जनवादी अधिकार ना रह कर वैध रूप से वैश्विक उत्पाद का रूप ले लेगी। छात्रों को उपभोक्ताओं तथा अध्यापकों को विक्रेता बना दिया जाएगा। बजट कटौती, नॉन नेट फैलोशिप को समाप्त करना, बेतहाशा फीस वृद्धियह सभी शिक्षा के प्रति इसी नजरिए का परिणाम है। तथा जब छात्र इन नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनके साथ किराए के गुण्डों की तरह बर्ताव किया जाता है। बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज का शिकार बनाया जाता है। नॉन-नेट फैलोशिप की समाप्ति के खिलाफ 9 दिसम्बर 2015 को हो रहे प्रदर्शन में शमिल छात्र-छात्राओं पर हमला इसका ज्वलंत उदाहरण है। एआईडीएसओ सभी शिक्षा प्रेमी लोगों से इन हमलों को पहचानने तथा इनके सही चरित्र को समझने की अपील करता है। ऐसे में समय की मांग है कि शिक्षा पर, विचार करने की प्रक्रिया तथा मानव सभ्यता पर हो रहे हमलों क खिलाफ आन्दोलन गठित किया जाए।

कलबुर्गी जिला कमेटी का 9वाँ छात्र सम्मेलन सम्पन्न

एआईडीएसओ की कलबुर्गी जिला कमेटी ने 7 नवम्बर को कन्नड संघ हॉल में 9वा छात्र सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में स्कूल, कॉलेज और विष्ठवविद्यालयों से आए हुए छात्रों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) पार्टी के जिला सचिव कॉ. एच.वी. दिवाकर ने किया। सम्मेलन की शुरूआत सर्वहारा के महान नेता और इस युग के अन्यतम मार्क्सवादी दार्शनिक एवं चिन्तनकार कॉ. शिवदास घोज़ की फोटो पर मार्ल्यापण करके हुई। कॉ. एच.वी. दिवाकर ने अपने उद्घाटन भाज़ण में कहा कि वर्तमान की सामाजिक-राजनैतिक स्थिति आज छात्र समुदाय को संघर्ज़ में शामिल होने और सत्य एवं न्याय की स्थापना करने की मांग करती है। सत्ता में आ जाने के बाद भाजपा सरकार ने शिक्षा बजट में कटौती कर रही है और शिक्षा में सांप्रदायिक पहलू को घुसा रही है।

एआईडीएसओ के कर्नाटक राज्य अध्यक्ष कॉ. वी.एन. राजाशेखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने शिक्षा में व्याप्त व्यापारीकरण और पास-फेल प्रणाली के समाप्त हो जाने से शिक्षा में अव्यवस्था पर अपनी बात रखी। उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित सभी छात्रों से एआईडीएसओ को सशक्त बनाने और छात्रों को आन्दोलन में शामिल होने की अपील की।

सम्मेलन में दो प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्य प्रस्ताव वर्तमान समय में शिक्षा पर होने वाले हमलों पर रोशनी डालता है। दूसरे प्रस्ताव में पिछली जिला कमेटी के द्वारा संचालित किए गए महत्त्वपूर्ण संघर्ज़ की रिपोर्ट का ब्योरा दिया गया।

अंत में एक जिला कमेटी का चुनाव किया गया।

नई कमेटी इस प्रकार है:

अध्यक्ष: मल्लीनाथ सिंघे, उपाध्यक्ष: विष्ठवनाथ भिमल्ली, अश्विनी ए, शरानबासु हेरूर

सचिव: हनमंत एस एच

सचिव मण्डली: अभय दिवाकर, रामलिंगप्पा बी. एन., ईराना इसाबा, अजय जाधव, मल्लीनाथ हुण्डेकल, स्नेहा कट्टीमणी

कार्यकारीणी: शिवुकुमार आन्दोला, शिल्पा बी.के., कीर्ती, साईदप्पा वाई.डी.जी., बसवंतराय इंगालागी, तुलजप्पा, रमेश एस.बी.डी.

जिला परिज्द: रश्मि, प्रवीण लण्डनकर, पुनीत, अम्बिका बी.के., शरत् गूगाल, राघवेन्द्र माणे, तेजस आर इब्राहीमपुर, काबेरी, दुर्गप्पा, विज्णु, रमेश, सुभाज़, सबारेड्डी, रेखा, रीना पंवार, श्वेता, रम्या

केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कन्वेंशन

शिक्षकों, छात्रों, शिक्षाविदों और शिक्षाप्रेमियों का यह कन्वेंशन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब वर्तमान केन्द्र सरकार और एक नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने की तैयारी में है। 31 अक्तूबर 2015 को जारी अपने आदेश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए कमिटी का गठन कर दिया है। कमिटी के अध्यक्ष हैं मंत्रीमंडल के पूर्व सचिव श्री टीएसआर सुब्रमनियम। इसके अन्य सदस्य हैं: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव श्रीमती शैलजा चन्द्रा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के पूर्व गृह सचिव श्री सेवाराम शर्मा, गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव श्री सुधीर मनकड तथा एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक प्रो. जे. एस. राजपूत। दिसम्बर तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विमर्श की प्रक्रिया पूरी होने की बात है।

आइए, प्रस्तावित शिक्षा नीति पर बात करने के पहले देश में अब तक जारी शिक्षा प्रणाली पर एक सरसरी नजर डाल ली जाय। सर्वविदित है कि शिक्षा ही मनुष्य को सिर ऊंचा कर खड़ा होने लायक बनाती है। तभी तो हम देखते हैं कि देश के पुनर्जागरण और आजादी आंदोलन के सेनानियों ने शिक्षा पर खास जोर देते हुए 'जनवादी, धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक' शिक्षा की मांग की थी। जनवादी शिक्षा के तहत जहां अमीर-गरीब, जाति-मजहब, लिंग आदि का भेद किये बगैर सभी को शिक्षा मुहैया होगी, वहीं शिक्षा की तमाम आर्थिक जिम्मेवारी सरकार की होगी। लेकिन छात्रों को क्या और कैसे पढ़ाया जायेगा, इसकी रूपरेखा शिक्षाविद् तय करेंगे, न कि नौकरशाह। शिक्षण संस्थानों की अपनी स्वायत्तता होगी। दूसरी तरफ शिक्षा धार्मिक प्रभाव से मुक्त और छात्रों के अंदर वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने वाली होगी। लेकिन इतिहास बताता है अलग-अलग युगों में शासकों ने अपने शासन को लम्बा और मजबूत करने के लिए हमेशा ही शिक्षा को खास निशाना बनाया है। उदाहरण के तौर पर हम पाते हैं कि अंग्रेज वायसराय लार्ड कर्जन ने 1804 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लागू किया था, जिसका उद्देश्य था उभरते राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित शिक्षित नौजवानों की भारी बढ़ोतरी को रोकना। कानून के जरिये उच्च शिक्षा में भारतीय छात्रों के प्रवेश को सीमित कर दिया गया था। दुखद पर सत्य है कि आजादी के बाद भारतीय शासक भी अंग्रेजी शासकों के ही पद चिन्हों पर चलने लगे। यूजीसी के प्रथम चेयरमैन दिवंगत सी. डी. देशमुख ने खुल्लमखुल्ला कहा था, ''हम शिक्षित बेरोजगारों की संख्या को कम करने के लिए उच्च शिक्षा को सीमित करना चाहते हैं।'' इसके बाद कॉलेजों-विश्वविद्यालयों में सीटों की संख्या में कटौती की नीति अपनायी गयी। फीस बढ़ाने, किताबों व अन्य पाठ्य सामग्रियों के दामों में बढ़ोतरी के जरिये धीरे-धीरे शिक्षा का खर्च बढ़ा दिया गया। फिर शिक्षा के लिए आवंटित बजट में कटौती की जाने लगी। इसी क्रम में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रीत्व में 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा 1986 में राजीव गांधी के जमाने में दूसरी शिक्षा नीति आयी। माना जाता है कि 1968 की नीति की पृष्ठभूमि में एक तरफ भारतीय संविधान एवं कोठारी आयोग की रिपोर्ट थी, तो दूसरी तरफ देशी एकधिकार घरानों को बढ़ावा देने वाली अर्थनीति। जबकि 1986 में लायी गयी नीति में काफी ताकतवर हो चुके भारतीय एकाधिकार घरानों के ही वृहद् स्वार्थ में नयी उदारवादी वैश्विक अर्थनीति का पूर्वानुमान दिखता है। तभी तो इसमें शिक्षा को 'निवेश का अनोखा क्षेत्र' (न्दपुनम पिमसक वि पदअमेजउमदज) कहा गया है। नतीजे हमारे सामने हैं। देश में निजी स्कूल-कॉलेज-विश्वविद्यालयों की बाढ़ आ गयी। बिड़ला-अंबानी कमिटी की रिपोर्ट में तो एकाधिकार पूंजीपतियों के स्वार्थ को नग्न रूप से आगे बढ़ाते हुए भूमंडलीकरण-निजीकरण-उदारीकरण के अभियान के तौर पर इस बात पर जोर दिया गया कि प्राथमिक स्तर के अलावा शिक्षा के किसी भी स्तर की जिम्मेवारी सरकार नहीं लेगी। उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों को धीरे-धीरे स्ववित्त पोषण का स्तर हासिल करना होगा। इस प्रकार शिक्षा को आवश्यक रूप से बाजार आधारित, बाजार से संबंधित और बाजार से संचालित खरीद-बेच की वस्तु माना जाने लगा। आगे चलकर 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा योजना (क्च्च्ब्) लायी गयी। इसने निजीकरण की प्रक्रिया को गति देते हुए इस बात पर जोर दिया कि ''नागरिकों को शिक्षा के बारे में अपने चयनों सहित अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है।'' इसका मतलब हुआ कि अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए खुद ही तौर-तरीके तलाशने होंगे चाहे वे दिन में दो वक्त का भोजन जुटाने की स्थिति में भी न हों। फिर विश्व बैंक द्वारा फंडिंग की गयी एक दूसरी योजना सर्व शिक्षा अभियान को लाया गया। सरकार द्वारा इस योजना को दी गयी मामूली राशि से यह साबित हो गया कि सरकार प्राथमिक शिक्षा से पल्ला झाड़ रही है। परिणामस्वरूप गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों की बड़ी संख्या स्कूलों से बाहर हो गयी। सरकारी स्कूलों का ढांचा अधिकाधिक लचर होता चला गया। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा इस दावे के साथ कि वह 'निःशुल्क और अनिवार्य' शिक्षा प्रदान करने के एक ऐतिहासिक संकल्प को कार्यान्वित कर रही है, शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 लाया गया। लेकिन देखा गया कि यह शिक्षा का अधिकार कानून बच्चों को न तो अधिकार प्रदान करता है और न ही शिक्षा। इस कानून को लागू करने के लिए राज्यों को बजट आवंटन के विषय में स्पष्ट अनुबंधों के अभाव में जब यह अनुपयुक्त और पंगु बनकर रह जाता है, तो इसकी मंशा पर भी सवाल उठ जाते हैं। इस कानून के लागू होने के बावजूद स्थिति यह है कि एक करोड़ 50 लाख बच्चे आज भी स्कूल के अहाते से बाहर हैं, जबकि छोड़ देने वाले (ड्राप आउट) बच्चों का प्रतिशत 46 है। देश भर में शिक्षकों के 1 लाख 40 हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं। 17,282 क्षेत्रों में 1 किलो मीटर के दायरे में अंदर एक भी स्कूल नहीं है। 1,48,696 स्कूलों के पास अपना खुद का भवन या किसी तरह का ढांचा नहीं है। 1,65,747 स्कूलों में पीने के पानी का कोई प्रबंध नहीं है। बिना शौचालय के 4,55,561 स्कूल चल रहे हैं। 1,14,531 प्राइमरी स्कूलों में केवल एक ही शिक्षक हैं। बुनियादी ढांचे की यह दयनीय तस्वीर है जो 2010 में किये गये एक सर्वेक्षण में सामने आयी है। साथ ही हम देख रहे हैं कि शिक्षा में वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत सहित कई देशों की सरकारें शिक्षा को एक 'वैश्विक उत्पाद' में परिवर्तित करने की लगातार कोशिश कर रही हैं। अमेरिका के नेतृत्व में ताकतवर साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा 1995 में विश्व व्यापार संगठन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर.....

(पृष्ठ 3 का शेष)

(ॅ्ज) की स्थापना और इसके अन्तर्गत ळॅै (जनरल एग्रीमेन्ट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज) समझौते के बाद अगस्त 2005 में भारत सरकार ने उच्च शिक्षा को ळॅै के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव रखा। और, अब 15-18 दिसम्बर को नैरोबी में होने जा रहे सम्मेलन में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति की मुहर लगने जा रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं शिक्षा अगर एक बार ळॅै के अन्तर्गत आ गयी तो यह 'जनवादी अधिकार' नहीं रह जायेगी और कानूनी तौर पर वह एक 'वैश्विक उत्पादन' में तब्दील हो जायेगी। ॅ्ज के अन्तर्गत शिक्षण संस्थान उन्हीं नियमों से संचालित होंगे, जिन नियमों से उद्योग संचालित होते हैं, जहां पर छात्र एक 'ग्राहक' और शिक्षक ग्राहक को लुभाने वाले एक 'विक्रेता' की भूमिका में होंगे। जिसका मतलब है कि देशी-विदेशी पूंजीपति सरकार के सहयोग और समर्थन से देश को लूटेंगे। इतना ही नहीं, कुछ साल पहले यूपीए के शासनकाल में कई शिक्षा विरोधी 'सुधार' किये गये। वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा बजट में कटौती, नॉन नेट फेलोशिप को समाप्त करना, बेतहाशा फीस वृद्धि आदि सभी शिक्षा विरोधी कदम हैं।

विस्तार में न जाकर भी हमें यह समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि तमाम शिक्षा नीतियों, आयोगों, कमिटियों व कानूनों के बावजूद स्थिति यह है कि शिक्षा हासिल करना आज गरीब, निम्न मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग परिवारों से आने वालें बच्चों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। सरकार शिक्षा की अपनी आर्थिक जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रही है। दूसरी तरफ शिक्षा को बाजारू माल में तब्दील कर अमीर तबके लिए आरक्षित कर दिया गया है। देश में शिक्षा से लैस ओर शिक्षा से महरूम दो तरह के नागरिक तैयार किये जा रहे हैं। छात्रों के अंदर वैज्ञानिक, तार्किक व विश्लेषणात्मक मानसिकता का निर्माण न हो सके-इस मकसद से पाठ्यक्रमों में धार्मिक, अवैज्ञानिक व अनैतिहासिक बातों को लाया जा रहा है। हाल के दिनों में मौजूदा सरकार द्वारा अपनी विचारधारा वाले खास लोगों को राष्ट्रीय ख्याति के शैक्षिक संस्थानों व विभिन्न बॉडियों/आयोगों में बैठाया जाना चिंता का विषय है।

आइए, अब हम इस परिप्रेक्ष्य में मौजूदा केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का थोड़ा अवलोकन कर लें। प्रस्तावित शिक्षा नीति के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो दस्तावेज जारी किये गये हैं, उनसे यह साफ नहीं है कि अचानक क्यों एक नयी शिक्षा नीति की जरूरत आ पड़ी। यहां न शिक्षा के बड़े उद्देश्यों का कोई जिक्र है और न ही पहले की नीतियों व योजनाओं का कोई मूल्यांकन। दस्तावेजों पर विमर्श के लिए तय की गयी समय सीमा भी बहुत कम है।

प्रस्तावित नयी शिक्षा नीति में कुल 33 विषय हैं। इनमें से 13 स्कूली शिक्षा के लिए हैं, तो 20 उच्च शिक्षा के लिए। विमर्श के लिए दिये गये बिन्दुओं में विज्ञान और गणित शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल तो दिया गया है, लेकिन साथ ही इस बात की स्वीकारोक्ति भी है कि विज्ञान और गणित शिक्षा में कमजोर होने के कारण कुल विद्यार्थियों में से 80 प्रतिशत विद्यार्थी दसवीं बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। साथ ही उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय में कम नामांकन और खराब गुणवत्तापरक शिक्षा को देश में वैज्ञानिक जनशक्ति (कार्मिकों) के विकास में आने वाली बाधा बताया गया है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर जोर देते हुए पूछा गया कि आपके राज्य में किस किस्म के व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपयोगी सिद्ध होंगे। यानी औपचारिक शिक्षा, जिसमें चरित्र निर्माण और मनुष्य निर्माण का तत्व रहता है; जनवादी मूल्यों और नैतिकता की बातें रहती हैं, अब उनकी विदाई हो जायेगी। यह मनुष्य को मशीन बनाने की साजिश नहीं तो क्या है? साथ ही इसमें समग्र सतत मूल्यांकन तथा अंकों के स्थान पर ग्रेड देने वाली पद्धति की वकालत की भी गयी है। दूसरे शब्दों में कहें, तो इसमें बेरोकटोक पास करने की नीति को ही जायज ठहराया जा रहा है। जबकि बेरोकटोक पास करने या स्वत:उत्तीर्ण होने की इस नीति के खामियाजे के तौर पर हम देख रहे हैं कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में काफी गिरावट आयी है। दस्तावेज में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक और जनवादी शिक्षा का कोई जिक्र नहीं है। हां, 'व्यापक शिक्षा-नीतिशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, कला, शिल्प और जीवन कौशल' शीर्षक के अंतर्गत स्कूली पाठ्यक्रम में मूल्यपरक (टंसनम)शिक्षा की बात कही गयी है। आशंका है कि इस मूल्यपरक शिक्षा में कहीं शिक्षा का भगवाकरण तो शामिल नहीं है।

उच्च शिक्षा के अंतर्गत 'सर्वश्रेष्ठ शिक्षक तैयार करना' शीर्षक विषय में कहा गया है कि स्थानीय शिक्षकों की नियुक्ति अनुबंध पर करें और उन्हें तैयार करें। जबकि 'निजी क्षेत्र के साथ सार्थक भागीदारी' शीर्षक विषय में पूछा गया है कि निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी किस प्रकार की जा सकती है। इसके लिए जो विकल्प सुझाए गये हैं, वे हैं: भवनों का निर्माण, केवल प्रयोगशालाओं और पुस्तकालय का निर्माण, भवन का अनुरक्षण, कॉलेज का अनुरक्षण, प्रयोगशालाओं का अनुरक्षण, छात्रावास, आईसीटी सुविधाएं, मनोरंजन, परिवहन इत्यादि। साथ ही यह भी पूछा गया है कि क्या पीपीपी मॉडल केवल तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा के लिए उपयुक्त है या सामान्य शिक्षा के लिए भी। इससे साफ है कि आने वाली शिक्षा नीति निजीकरण को बढ़ावा तो देगी ही। साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति भी अनुबंध पर होगी। 'उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण' शीर्षक विषय में पूछा गया है कि क्या विदेशी शिक्षा प्रदाताओं को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इस सवाल के साथ यदि भारत सरकार द्वारा ॅ्ज और ळॅै में शामिल होने की बात को जोड़ लिया जाय तो, जो अर्थ निकलता है वह यह कि शिक्षा में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की घुसपैठ और सुगम होगी। नतीजतन शिक्षा आम लोगों के लिए दुर्लभ बन जायेगी। इतना ही नहीं, निजी-लोक साझेदारी के लिए बेहतर नीति बनाने, छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे देशों में आने-जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। 'निजी क्षेत्र के साथ सार्थक भागीदारी' शीर्षक में कहा गया है कि उच्च शिक्षा केवल सरकारी खर्च से नहीं चल सकती। निजी मालिकों के साथ और सार्थक भागीदारी पर बल देते हुए पीपीपी मॉडल को जारी रखने का परामर्श दिया गया है। 'उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय व्यवस्था' के तहत बताया गया है कि जीडीपी का लगभग 1 प्रतिशत ही उच्च शिक्षा पर खर्च होता है, जबकि इसका लक्ष्य 1.5 प्रतिशत का है। यहां जीडीपी की बात कहकर केन्द्रीय बजट द्वारा आवंटन की बात को दबा दिया गया है। यानी छिपे तौर पर सरकार अपनी वित्तीय जवाबदेही से मुकर रही है। 'उच्च शिक्षा में कौशल विकास को जोड़ना', 'खुले और दूरस्थ शिक्षा के साथ ऑनलाइन कोर्सेज को बढ़ावा', 'प्रद्योगिकी आधारित शिक्षण संस्थान' तथा 'उद्योग के साथ रोजगार की दृष्टि से जोड़ना' आदि शीर्षक इस बात के साफ संकेत हैं कि उच्च शिक्षा में ज्ञान की खोज, शोध को बढ़ावा देने की जगह प्रौद्योगिकी के उपयोग और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। इससे मौलिक शोधों पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

चर्चा और विमर्श के लिए दिये गये दस्तावेजों से जाहिर है कि प्रस्तावित नयी शिक्षा नीति द्वारा देश में चल रही शिक्षा विरोधी नीतियों में कोई खास बदलाव तो होगा ही नहीं, बल्कि बची-खुची शिक्षा भी खत्म हो जायेगी। सरकार शिक्षा पर खर्च की जिम्मेवारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ लेगी और उसे निजी मालिकों के हवाले कर दिया जायेगा।

यह सच है कि देश में शिक्षा की दुर्दशा एक बहुत ही दुखद तस्वीर पेश कर रही है। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी भी है। शिक्षा पर लगातार हो रहे हमलो ने छात्रों, शिक्षको, शिक्षाविदों और शिक्षाप्रेमियों को एक साथ विरोध के मंच पर ला खड़ा कर दिया है। हाल के दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय में थ्ल्न्ध् के खिलाफ आंदोलन की जीत का उदाहरण भी मौजूद है। इधर कई दिनों पहले अपने प्रांत में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पीजी नामांकन शुल्क में की गयी बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ छात्रों के आंदोलन ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पुराने शुल्क पर ही नामांकन करने को विवश कर दिया है। छात्रों, शिक्षकों, शिक्षाविदों और शिक्षाप्रेमियों का यह कन्वेंशन सरकार की प्रस्ताविक नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ अपना प्रतिवाद दर्ज कराते हुए उसे वापस लेने की मांग करता है। साथ ही कन्वेंशन सरकार से मांग करता है कि सरकार ऐसी शिक्षा नीति अपनाये जिससे 'शिक्षा सबके लिए' का नारा हकीकत में तब्दील हो सके।

जमीन हड़पने, जल स्रोतों पर कब्जों और विस्थापन के खिलाफ आयोजित साझा सम्मेलन में एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट)

4 नवम्बर 2015 को म.प्र. की राजधाानी भोपाल में आयोजित राज्यस्तरीय साझा सम्मेलन में एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) ने भागीदारी की। स्थानीय गाँधी भवन में आयोजित सम्मेलन मधयप्रदेष्ठा के लगभग 25 वामपंथी व जनवादी संगठनों के आ]वान पर आयोजित किया गया। इसमें मधयप्रदेष्ठा के विभिन्न क्षेत्रें में बाँधा व अन्य नाम पर जबरन भूमि अधिग्रहण तथा विस्थापन की समस्या से ग्रसित लोंगो ने भाग लिया। जबलपुर का चुटका परमाणु संयंत्र, कटनी में पावर प्लांट के नाम पर जबरन भूमि अधिग्रहण, सीधाी, सिंगरौली, सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, भिण्ड, मुरैना आदि अनेक जगहों से आये संघर्ज़्ष्ठील लोंगो ने अपनी समस्यायें रखी।

सम्मेलन को सी.पी.आई.द्धएम.ऋकी पोलित ब्यूरों सदस्य कॉ.सुभाज़्ीनि अली एस.यू.सी.आई.द्धसी.ऋ के राज्य सचिव कॉ.प्रताप सामल, सी.पी.आई.द्धएम.ऋ के राज्य सचिव कॉ.बादल सरोज, सी.पी.आई के राज्य सचिव कॉ.अरविन्द श्रीवास्तव, जानी मानी समाजसेविका मेधाा पाटकर, वरिज़्ठ पत्र्कार श्री एल.एस. हरदेनिया, हाल ही में बढ़ती असहिज़्णुता के खिलफ अपना साहित्य अकादमी पुरूस्कार लौटाने वाले जाने माने साहित्यकार श्री राजेष्ठा जोष्ठी व डॉ.सुनीलम सहित मधयप्रदेष्ठा के अन्य प्रबु)जनों ने संबोधित किया। इसके बाद 11 जनवरी से 19 जनवरी तक एक प्रदेष्ठा व्यापी यात्र निकालने तथा 24 ऱरवरी को दिल्ली में होने वाले राज़्ट्रीय प्रदर्ष्ठन में सम्मिलित होने सहित कई अन्य कार्यक्रम लिये गये।

देश भर में सद्भावना दिवस.....

(पृष्ठ 2 का शेष)

उपयुक्त नहीं है। वे भूल गए कि संसद जिनकी वे बहुत तारीफ करते हैं और उसका पालन करते हैं उसका जन्म भी यूरोप में ही हुआ न कि भारत में। इस प्रकार की सारी भ्रांत धारणाएं जनता में भ्रान्तियाँ पैदा कर रही हैं। इन सबके विरोध में जनता में जनवादी धारणा सृष्टि करना सही वामपंथी पार्टियों तथा ताकतों के द्वारा ही संभव है। तभी हम वामपंथी एएवं जनवादी पार्टियाँ एक साथ होकर इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं जिसमें आप सभी को शामिल होना होगा। देश की सारी जनवादी ताकतों से हम अपील करते हैं कि सभी इस आन्दोलन में पूरी ताकत के साथ शामिल हो जाएं। आपके सामने मैं उन स्थिति का विश्लेषण किया है ये स्थिति का एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू भी आप लोगों को खयाल रखना चाहिए। आज पूँजीवादी व्यवस्था अपने चरम संकट पर पहुँच चुकी है। इसका तमाम बोझ जनता के कंधे पर डालकर सरकार पूँजीपतियों की ही सेवा कर रही है। वो वास्तव में इस संकट के सृष्टिकर्त्ता हैं, जो शोषक हैं, ये सरकार उनकी ही सेवा कर रही है। उनके ही हित के लिए सारी नीतियाँ बनाई इन सबके विरोध में जनता के मन में जो विक्षोभ पैदा हो रहा है। वो स्वत:स्फूर्त रूप से विक्षोभ से फूट रहा है। दिल्ली विध

ानसभा चुनावों में, यू.पी. के पंचायत चुनाव मे, बिहार विधानसभा चुनाव में और अभी अभी गुजरात में हुए पंचायत चुनावों के नतीज देखने से आपको पता चल जाएगा।

इस विक्षोभ को संगठित रूप देना होगा। स्वत:स्फूर्त आन्दोलन को संगठित रूप ना देने से एवं सही दिशा न देने से वो जो फूट पड़ता है वैसे हो भी हो जाता है। ये वामपंथी दलों का काम है। इसीलिए देश के सारे वामपंथी दलों को एकजुट होकर इस आन्दोलन को शुरू किया है। अत: मैंने आप लोगों से एक चीज समझनेके लिए कहूँगा कि सारी बुर्जुआ पार्टियाँ आम जनता को बांटने के लिए बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, ऊँची जात और नीची जात की बातें करके गुमराह करते है। और हमें आपस में लड़ाते हैं आप लोगों को समझना होगा कि मजदूर वर्ग के बीच में, शोषक एवं शोषितों के बीच में, पँजीपति वर्ग मजदूर का शोषण करती है। ये तो महज बात है, उसमें में धर्म या जात-पात की परहवाह नहीं करते। बिरला बहुत बड़ा हिन्दू है, बिड़ला मंदिर प्राय: सभी शहरों में देखने को मिलता है लेकिन सिर्फ मुसलमान या इसाई मजदूर का ही शोषण करते हैं क्या वे ऐसा कभी कहेंगे कि हम हिन्दू मजदूर का शोषण नहीं करेंगे। वो जैसे बौद्ध मजदूर का शोषण करते हैं उसी रूप में हिन्दू मजदूर का शोषण करते हैं। इसलिए शोषित जनता को समझना होगा कि वो जात-पात धर्म मजहब की बात करके मजदूरों में फूट डालते हैं। वे मेहनतकश जनता के दुश्मन हैं। हमें समझना चाहिए कि हम हिन्दू, मुसलमान या इसाई घर में जन्म लिया है लेकिन हैं तो शोषित। हमें एक साथ पूँजीवाद के साथ लड़ाई लड़नी है। इसी रास्ते से हमें एक दिन शोषण के शासन से मुक्ति मिल पाएगी। मुसलमान या इसाई भाईयों से हम कहेंगे कि आप यदि खुद को मुसलमान या इसाई तो आप निश्चित रूप से अल्पसंख्यक हो लेकिन यदि आप खुद को शोषित पीड़ित मजदूर के रूप में समझो तो आप बहुसंख्यक है। किसी भी पूँजीवादी देश में मजदूर एवं मेहनतकश जनता ही बहुमत में है। 90% जनता मजदूर एवं मेहनतकश है और यही वास्तव है। आप सब इसी रास्ते पर चलेंगे। इसी उम्मीद के साथ में अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ।

मुरादाबाद, उ.प्र.: वामदलों के राष्ट्रव्यापी साम्प्रदायिकता वरोिधी अभियान (एक से छ: दिसम्बर) के तहत मुरादाबाद की चार वामपंथियों पार्टियों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर आज रेलवे स्टेशन से कचहरी तक जुलूस निकाल कर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, भारत सरकार को ज्ञापन भेजा गया तथा जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे। साम्प्रदायिकता की राजनीति बन्द करो, साम्प्रदायिक बयान देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करो, समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को तहस-नहस करना बंद करो, शिक्षा-संस्कृति का भगवाकरण नहीं चलेगा, साहित्यकारों, कलाकारों पर हमले बन्द करो। ज्ञापन में मांग की गई कि साम्प्रदायिक नफरत फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। तथा देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक जनवादी मूल्यों की रक्षा की जाए। जुलुस का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवाद) के कॉमरेड ब्रह्मस्वरूप, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया के कॉ. नैम सिंह, भाकपा (माले) के कॉ. रोहतास राजपूत तथा सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) के हरकिशोर सिंह ने किया। वक्ताओं ने कहा कि आज साम्प्रदायिक आर.एस.एस.-बीजेपी तथा शिवसेना संघ परिवार साम्प्रदायिक तनाव से माहौल गरमाने, विभिन्न सम्प्रदायों के बीच फूट डालने तथा अंधता फैलाने का कुचक्र रच कर देश में फासीवाद लाना चाहते है। चुनाव के समय देश के आम जनमानस को अच्छे दिन के सपने दिखाए। और अब कॉरपोरेट घरानों की जेबें भर रहे हैं। देश की आम जनता इसके खिलाफ न उठ खड़ी हो इसलिए उनकी एकता को तोड़ा जा रहा है। साहित्यकारों, कलाकारों तथा सही सोच रखने वाले लोगों की हत्या की जा रही है। उच्च पदों तथा मंत्री पद पर बैठे लोगों के द्वारा अनाप-शनाप बयान दिए जा रहे हैं। वक्ताओं ने इसके खिलाफ उठ खड़े होने तथा जोरदार प्रतिवाद आन्दोलन खड़ा करने का आह्वान किया। वक्ताओं ने पुरस्कार लौटाने वाले मुरादाबाद के मशहूर चित्रकार डॉ. नरेन्द्र सिंह के प्रति भी आभार प्रकट किया। सभा को विजयपाल सिंह, डॉ. राहत जमा खां, मो. गौरी, कमलेश चहल, डॉ. नरेन्द्र सिंह, फैज़ खां, इस्लाम अली, सुरेशपाल सिंह आदि ने भी सम्बोधित किया।

जौनपुर, उ.प्र. 6 दिसम्बर 2015 को जौनपुर में वामपंथी संघर्ष समिति के आह्वान पर एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट), सी.पी.आई., सी.पी.एम. पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्त्ताओं ने संयुक्त रूप से जुलूस निकाला। समाज में आपसी एकता बनाए रखने का संदेश देते हुए नारे लगाते हुए जुलुस चल रहा था। सामाजिक सद्भाव कायम करो, साम्प्रदायिकता फैलाने वाली ताकतों का बहिष्कार करो, अभिव्यक्ति की आजादी कायम करो, धर्म के नाम पर उत्पीड़न बन्द करो। देशमें बढ; रही असहिष्णुता व हत्याओं पर रोक लगाओ। वामपंथी ताकत जिन्दाबाद, इत्यादि नारे लगाए जा रहे थे। रैली पॉलिटैक्निक चौराहा से चल कर रूहट्ठा, ओलन्दगंज, चहारसू होते हुए दीवानी स्थित अम्बेडकर पार्क में पहुँचकर सभा के रूप में बदल गइ। रैली को एस.यू.सी.आई.(सी) के जिला सचिव कॉ. जगदीशचन्द्र अस्थाना, प्रवीणकुमार शुक्ल, मिथिलेश मौर्य, सीपीआई(एम) जिला सचिव किरण शंकर सिंह, जयप्रकाश सिंह, विजय प्रताप सिंह, सीपीआई के जिला सचिव कल्पनाथ गुप्त ने सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष मण्डल के सदस्यों कॉ. जगदीशचन्द अस्थाना (एसयूसीआई(सी)), कल्पनाथ गुप्त(सीपीआई) किरण शंकर सिंह (सीपीएम) व संचालन कॉ. सुभाषचन्द्र ने किया। कार्यक्रम के शुरू में कॉमसोमोल की छात्रा कॉ. अनीता ने एक क्रान्तिकारी गीत पेश किया।

इलाहाबाद, उ.प्र.: असहिज्णुता के पक्ष में और असहिज्णुता खिलाफ छ: प्रमुख वामपंथी दलों के देशव्यापी साम्प्रदायिकता विरोधाी अभियान के अन्तर्गत इलाहाबाद में 1 से 6 दिसम्बर तक नगर के छ: प्रमुख स्थलों पर घरना दे कर, जनता के बीच अपनी बात को ले जाने का छ: दिनी कार्यक्रम लिया गया। इसके अन्तर्गत 1 दिसम्बर को अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की प्रतिमा (कम्पनी बाग), शहीद लाल पद्मधर की प्रतिमा (कचहरी), शहीद रोशन सिंह की प्रतिमा (स्वरूप रानी अस्पताल), अम्बेडकर प्रतिमा (हाईकोर्ट चौराहा), नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा (सिविल लाइन्स) तथा महात्मा गांधी की प्रतिमा (बालसन चौराहा) पर धारना आयोजित किया गया। धारने के अवसर पर आयोजित सभाओं में

एस0यू0सी0आई0(सी0), सी0पी0आई0 (एम0), सी0पी0आई0 तथा सी0पी0आई0 (एम0एल0) के नेताओं ने क्रमानुसार अधयक्षता की। शहीद रोशन सिंह की प्रतिमा तथा शहीद लाल पद्मधार की प्रतिमा पर आयोजित सभाओं की अधयक्षता एस0यू0सी0आई0(सी0) के जिला सचिव कॉ0 एस0के0मालवीय ने की। इन

देश भर में सद्भावना दिवस.....

(पृष्ठ 5 का शेष)

सभाओं में सी0पी0आई0 द्धएम0ऋ के जिला सचिव का0 रवि मिश्रा, सी0पी0आई0 के जिला सचिव का0 राज कुमार जैन, सह सचिव कॉ0 नसीम अंसारी तथा सी0पी0आई0 द्धएम0एल0ऋ के जिला सचिव कॉ0 राध ोश्याम मौर्य तथा पोलित ब्यूरो सदस्य का0 रामजी राय के अतिरिद्र अनेक वद्राओं ने अपने विचार रखे। वद्राओं ने कहा कि भाजपा, आर0एस0एस0 और उसके अन्य संगठनों के द्वारा देष्ठा में अंधाविष्ठवास और धार्मिक उन्माद ैला कर, जो असहिज्णुता और हिंसा का वातावरण बनाया जा रहा है, उसका उद्देष्ठय देष्ठा की गंगा.जमुनी संस्कृति को नज़्ट करके जनता में ूट डालना है, ताकि जनता का धयान महंगाई, बेरोजगारी, भ्रज़्टाचार आदि की जनता की असली समस्याओं से उसका धयान हटाया जा सके और देष्ठाी.विदेष्ठाी पूंजी के द्वारा उसको बेरोक.टोक लूटा जा सके। वद्राओं ने, मोदी सरकार के द्वारा देष्ठा को साम्प्रदायिक-फासीवाद की ओर धाकेलने की साजिष्ठा से आगाह किया और छः वाम दलों की एकता को समय अवष्ठयकता बताते हुए सभी वाम, जनतांत्रिक और प्रगतिष्ठाील ताकतों से एकजुट होने का आ]वान किया। धारने में एस0यू0सी0आई0 द्धसी0ऋ की जिला इकाई के, कॉ0 कमलेष्ठा, सुमन ष्ठुक्ला, राजवेन्द्र सिंह, झरना मालवीय, विनोद यादव, आष्ठाू ठाकुर, निर्मल कुमार, आनन्द, सि)ार्थ, आरि, जुबैर अहमद, रामपति, संध्या मिश्रा, रेनू गुप्ता, रष्ठिम मालवीय आदि ने बढ़.चढ़ कर हिस्सा लिया।

रिवाड़ी, 6 दिसम्बर, एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) के तत्वावधान में साम्प्रदायिकता के विरोध में एकजुटता दिवस मनाया गया। पार्टी कार्यकर्त्ता एवं प्रबुद्ध नागरिक स्थानीय राव तुलाराम पार्क में इकट्ठे हुए और सभा का आयोजन किया, प्रतीक के तौर पर साम्प्रदायिकता का पुतला फूँका। सभा के मुख्य वक्ता एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) के जिला सचिव कॉमरेड राजेन्द्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद 'फूट डाला राज करो' की नीति से संचालित था ताकि देश की जनता आजादी के लिए एकजुट ना हो सकें, ब्रिटिशशाही धार्मिक कट्टरता को पनपा कर साम्प्रदायिक दंगों को बढ़ावा देती थी, परन्तु आजादी के बाद सरकारों ने 'फूट डालों राज करो' की नीति का ही अमल किया है, भाजपा की सरकार के सत्तासीन होने के बाद देश में साम्प्रदायिक दंगे बढ़ें हैं, आपसी सोहार्द में टूटन आई है, इसके पीछे सरकार का उद्देश्य है कि देश की जनता पूँजीपतियों के पक्ष में पारित नीतयों के खिलाफ एकजुट ना हो सकें, पूँजीपतियों की लूट बरकरा रहे, वर्ग संघर्ष तेज हो की बजाए बनावटी सवालों पर देश की जनता उलझी रहे। इस अवसर पर प्रो. अनिरुद्ध यादव, कृषक खेत मजदूर संगठन के नेता राकुमार, ऑल इण्डिया यूटीयूसी के प्रधान अमृतलाल बलराम, डी.वाई.ओ. अनिल अजय, नरेश, जसवन्त अमरसिहं इत्यादि ने अपने विचार प्रकट किए।

हैदराबाद: वामपंथी पार्टियों ने 6 दिसम्बर 2015 को साम्प्रदायिकता के खिलाफ एक सम्मेलन का आयोजन किया। सीपीआई(एमएल) एनडी के कॉ. वी. वैण्कटरमैया ने सभा की अध्यक्षता की। हाई कोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस चन्द्रकुमार ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। एस. यू.सी.आई.(सी) की तेलांगा-आंध्र प्रदेश राज्य की सांगठनिक कमेटी के सचिव कॉ. के. श्रीधर के साथ साथ सीपीएम के राज्य सचिव कॉ. टी. वीरभद्रम, सीपीआई के राज्य सचिव कॉ. चड्ढा वैण्कट्टारेड्डी ने सभा को सम्बोधित किया। आर.एस.पी. के जानकी रामलू, एआईएफबी के कॉ. सुरेन्द्र रैड्डी और एमसीपीआई(यू) के कॉ. उपेन्द्र, सीपीआई के अज़ीज़ बाशा और एस.यू.सी.आई.(सी) के कॉ. चौधरी मुराहारी भी मंच पर उपस्थित थे। कॉ. के. श्रीधर ने कहा कि भारतीय पूँजीपति वर्ग मेहनतकश वर्ग की क्रान्ति से डरकर फासीवादी विचारधारा को प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने कॉ. घोष की उस चुनौती को याद कराया कि हालांकि दूसरे विश्वयुद्ध में फासीवाद हार गया था लेकिन विश्व में आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर से यह व्याप्त है। पूँजीपति वर्ग आधुनिक तकनीक को उत्पादन के लिए प्रयोग करता है। लेकिन संस्कृति के क्षेत्र में अंधविश्वास, पूर्वाग्रहों एव पुरातन समय के विचारों को फैलाता है। जनता के बीच अंधता और कट्टरपंथ को फैलाकर उनके प्रति गहन असहिष्णुता पैदा कर रहा है जो दूसरे धर्म, संस्कृति, जातियें, क्षेत्रों या पार्टियों और अंतिम रूप से दूसरे देशों के हैं। उन्होंने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी भी अप्राकृतिक सत्ता को मान्यता न देना होता है। यदि एक देश सभी ध र्मों को मानता है तो वह बहुधर्मतांत्रिक सत्ता बन जाता है। यदि एक देश किसी एक धर्म को मान्यता देता है तो वह धर्मतांत्रिक देश कहलाता है। किसी भी रूप से यह एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। उन्होंने कहा कि आज वाम पार्टियों को धर्मनिरपेक्षता की सही धारणा को फैलाने का कार्यभार लेना होगा और वाम-जनवादी आन्दोलन ही साम्प्रदायिकता के फैलने के खतरे का एकमात्र उपाय है। अन्यथा जनता छद्म-धर्मनिरपेक्षता के जाल में फंस जाएंगे।

विशाखापाटनम में एस.यू.सी.आई.(सी), सीपीआई(एम), सीपीआई ऑर एमसीपीआई(यू) ने 4 दिसम्बर 2015 को एक विरोध रैली के आयोजन की योजना बनाई थी परन्तु तेलुगु देशम पार्टी नीत आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के निर्देशों के चलते पुलिस प्रशासन ने एक शान्तिपूर्ण प्रतिवाद रैली की आज्ञा नहीं दी। पुलिस की चेतावनियों के बावजूद वाम पार्टियों कार्यकर्त्ता रैली निकालने के निश्चित समय पर सरस्वती पार्क पहुँच गए। जैसे ही प्रदर्शनकारी शान्तिपूर्ण रूप से एकजुट होकर साम्प्रदायिकता के खिलाफ नारे लगाने लगे वैसे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच कार्यकर्त्ताओं ने पुलिस के गैर-जनवादी रवैये के खिलाफ नारे लगाए। एस.यू.सी. आई.(सी) के विशाखापाटनम जिला इंचार्ज कॉ. एस. गोविन्द राजलु, सीपीआई(एम) के राज्य सचिव मण्डलीय सदस्य कॉ. चौधरी नरसिंहा रॉव, सीपीआई के सहायक राज्य सचिव कॉ. जे.वी. सत्यनारायण मूर्ती, एमसीपीआई(यू) के विशाखापाटनम के जिला सचिव कॉ. एम.वी.एन.आर. पटनायक और अन्य नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार किया गया। वामपंथी पार्टियों के नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई की निन्दा करते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जनवादी अधिकार पर एक हमला बताया। उन्होंने उत्पीड़ित जनता से सम्प्रदायों और जातियों से ऊपर उठकर जनता की एकता की रक्षा और एक जनजीवन की समस्याओं के खिलाफ एक सशक्त जनवादी आन्दोलन गठित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि एकमात्र वाम एवं जनवादी आन्दोलन ही धार्मिक कट्टरपंथ और फासीवाद के खतरे को चुनौती दे सकता है।

'मूवमेण्ट फॉर सेक्यूलर डेमोक्रेसी' ने 67वाँ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस

मूवमेण्ट फॉर सेक्यूलर डेमोक्रेसी (एम.एस.डी.) ने पीपुल्स युनियन फॉर सिविल लिबर्टीस (पी.यू.सी.एल.), गुजरात सर्वोदय मण्डल, अहमदाबाद वूमेन्स एक्शन ग्रुप (ए.डब्ल्यू.ए.जी.) ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (ए.आई.एम.एस.एस.), अहमदाबाद मुसलिम वूमेन्स एक्शन ग्रुप (ए.एम.डब्ल्यू.ए.), मजूर महाजन संघ (महिला विंग), पुनरूत्थान महिला संघ, प्रशांत, दर्शन सेण्टर फॉर डेवेलपमण्ट, गुजरात लोक समिति, वूमेन्स इण्टरनेशनल लीग फॉर पीस एण्ड फ्रीडम (डब्ल्यू.आई.एल.पी.एफ.) तथा अन्य संगठनों व लोगों के साथ मिलकर 10 दिसम्बर 67वाँ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस सरदारबाग, अहमदाबाद में मनाया।

1948 में मानव अधिकारों की सार्वत्रिक घोषणा के बाद से यह दिन देश भर में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। यह विडम्बना है कि मानव अधिकारों की घोषणा के 67 वर्ष बाद भी मानव अधिकारों की स्थिति बद से बदतर ही हुई है। यू.एन. मानव अधिकार उच्च अधिकारी ने वर्ष 2006 में यह देखा, '..... गरीबी मानव अधि कारों की सबसे बड़ी दुश्मन है। गरीबी का निवारण न ही कोई परोपकार है और न ही किसी देश की समृद्धि के आधार पर हो सकता है। इसे मानव अधिकारों की जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए। इस वर्ष मानव अधि कार का नारा है 'हमारे अधिकार, सदैव हमारी आजादी।''

कार्यक्रम में गीत, नाटक प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया गया। निम्न बिन्दुओं पर एक प्रस्ताव पास किया गया।

'10 दिसम्बर–67वें अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर, यह सभा महसूस करती है कि हमारे देश में मानव अधिकारों की हालत अत्यंत दयनीय है। हमारे देश में, 10% अमीर लोग 50% प्रदूषण फैलाते है; विश्व का हर 13वाँ कैंसर रोगी भारतीय है, अज्ञानता की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है; 6 सबसे ज्यादा एड्स से प्रभावित देशों में भी भारत दूसरे स्थान पर है; 2014 में लगभग 34 किसान हर दिन आत्महत्या करते थे, लगभग 135356 महिलाएं व 61444 बच्चे हमारे देश में गुमशुदा है। हर 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति मानसिक रोगी, एस.ई.ज़ेड द्वारा ली गई 90% जमीन का कोई उपयोग नहीं किया गया है, लगभग डेढ़ लाख लोग हर वर्ष सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं।

गुजरात में भी, एक साल में 7225 लोगों ने आत्महत्या की, सीपीसीबी के अनुसार 20 नदियाँ जहरीली हो गई; शराबखोरी पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद साढ़े छः साल में 327 करोड़ की शराब जब्त की गई; 47% परिवारों के पास अब तक शौचालय की सुविधानहीं है; सत्र अदालतों में अपूर्ण मामलों के लिए गुजरात तीसरे नम्बर पर आता है; आर.टी.आई सक्रिय लोगों की हत्या के लिए गुजरात पहले नम्बर पर है; 30 टोल बूथों पर 2रू प्रति कि.मी के हिसाब से टो टैक्स वसूला जा रहा है। ऐसी स्थिति में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए जनवादी आन्दोलन को बढ़ाने की जरूरत है। कार्यक्रम का अंत कैण्डल मार्च व 'हम होंगे कामयाब' गीत के साथ किया गया।

''साम्राज्यवाद–आतंकवाद'' विषय पर सेमिनार

मुरादाबाद, उ.प्र.: जिला कमेटी ने 29 नवम्बर 2015 को जलकल कार्यालय में ''साम्राज्यवाद–आतंकवाद'' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। जिसकी अध्यक्षता संगठन की जिलाउपाध्यक्षा कॉ. बबिता सिंह ने की तथा संचालन सचिव मो. गौरी ने किया। सेमिनार में मुख्य रूप से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कॉ. हरकिशोर सिंह महाराजा हरीशचन्द्र डिग्री कॉलेज के प्रो. व प्रख्यात चित्रकार नरेन्द्र सिंह, के.जी.के. डिग्री कॉलेज के प्रो. हिन्दी विभाग के अध्यक्ष डॉ. चन्द्रभान यादव, अविनाशचन्द्र सक्सेना, कमलेश चहल आदि ने विचार रखे। इस अवसर पर कॉ. हरकिशोर सिंह ने कहा कि आज पूरी दुनिया में साम्राज्यवादी अमेरिका की अगुआई में उसके जंगखोर दोस्त युद्ध छेड़े हुए हैं। और दुनिया का नए सिरे से बंटवारा करना चाहते हैं और संभव है कि ये तीसरे विश्वयुद्ध में बदल जाए। जिससे पिड़ित देशों की जनता अभूतपूर्व यातनाएं झेल रही है। ये साम्राज्यवादी मुल्क पूरी दुनिया में कमज़ोर देशों की हर तरह की सम्पदा को लूटने के लिए तबाही मचा रहे हैं। और उन देशों के अन्दर हर तरह के दंगे कराकर बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि साम्राज्यवाद ही असल में आतंक वाद का जनक है। यदि हम दुनिया मं शान्ति चाहते हैं तो पूँजीवाद–साम्राज्यवाद विरोधी शान्ति आन्दोलन को तेज करना होगा। इसके लिए युवाओं को आगे आना होगा। वक्ताओं ने आगे कहा कि सैन्य ताकत के बल पर निर्दोष जनता की हत्या की जा रही है। इसकी हम निन्दा करते हैं। ये साम्राज्यवादी मुल्क ही आतंकवाद पैदा कर रहे हैं और ये ही आतंकवाद को खत्म करने का ढोंग कर रहे हैं। आतंकवाद की आड़ में दूसरे देशों की सीमाएं लांघना भी उचित नहीं है। इससे आम जनता प्रभावित होती है। हम हर प्रकार के हमले का विरोध करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी देश सोवियत संघ में समाजवाद के ढहने का पूरी दुनिया पर बुरा प्रभाव पड़ा है और इससे साम्राज्यवादी अमरीका व अन्य जंगखोर देश खुले आम दुनिया में बर्बरता कर रहे हैं। जब तक समाजवादी खेमा कायम था तब तक इन देशों की किसी भी मुल्क पर हमला करने की हिम्मत नहीं थी। यदि इस सब से निजात पाना है तो पुन: समाजवाद स्थापित करना होगा तभी दुनिया सुरक्षित व जनता शान्ति से रह सकती है। सेमिनार में मंजू मेहता, नवीन वारसी, संजय तोमर, विनोद विग, नवाब अली, श्याम सुन्दर, मुख्तार अहमद, फैज़ खान, आदि ने सम्बोधित किया।

महान क्रान्तिकारी अमर शहीद खुदीराम बोस का 126वाँ जन्म दिवस मनाया गया

3 दिसम्बर 2015: ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में पिलानी के विभिन्न स्थानों राजपुरा, गंगा कॉलोनी तथा वालमीकि बस्ती में आजादी आन्दोलन की गैर समझौतावादी धारा के महान क्रान्तिकारी अमर शहीद खुदीराम बोस का 126वाँ जन्म दिवस पूरे जोशो–खरोश के साथ मनाया गया। वाल्मीकी बस्ती में सभा की अध्यक्षता श्री विश्वनाथ लाहोरा ने की। खुदीराम बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। एआईडीवाईओ के डॉ. रविकांत पाण्डे ने तथा कॉ. राजेन्द्र सिहाग ने अपने वक्तव्य रखे तथा शहीद के जीवन संग्राम की चर्चा की। सभा में अशोक चावरिया, मुकेश चावरिया, विक्रम चावरिया, ललित ढण्डवाल, सुन्दर ढेण्डवाल, विकास लाहोरा, मनोज लाहोरा, अनिल लाहोरा, संदीप लाहोरा, पंकज, राजेश पंवार, जगदीश, प्रमोद, दयानंद, आकाश, सूरज तथा अन्य लोग उपस्थित थे। राजपुरा में सभा की अध्यक्षता कमलेश ने की। महेन्द्र, गोविन्द, हरिराम तथा अन्य लोग भी उपस्थित थे। सभा का संचालन हरिराम ने किया। वक्तव्य विष्णु ने रखा। गंगा कॉलोनी में सभा की अध्यक्षता फणि तथा संचालन व वक्तव्य विष्णु ने रखा।

20 नवम्बर को रेल्वे के न्यूनतम किराया 5रू से 10रू किये जाने, टिकिट रद्दीकरण का शुल्क 15रू से 30रू किये जाने,रिर्जव टिकिट का रद्दीकरण शुल्क में की गई वृ) तथा रेल्वे में अन्य मदों में वृ) व ए.डी.आई. के विरू) एस.यू.सी.आई.द्धसी.ऋ के आ]वान पर बुलाये गये अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस के दिन मधयप्रदेष्ठा में राजधानी भोपाल सहित गुना,ग्वालियर,इंदौर,आदि ष्टाहरों में विरोधा के कई कार्यक्रम लिये गये। गुना में स्टेष्ठान पर कार्यकर्ता एकत्रि हुये व जबरदस्त नारेबाजी के साथ परिसर में विक्षोभ सभा हुई,जिसको पार्टी के राज्य सांगठिनक समिति सदस्य कॉ.लोकेष्ठा ष्टार्मा ने संबोधित किया तथा संचालन जिला कमेटी सदस्य कॉ.योगेष्ठा धााकड़ ने किया। बाद में एक ज्ञापन स्टेष्ठान मैनेजर के माधयम से रैल मंत्री को भेजा गया। ग्वालियर में प्रदर्ष्ठान ूलबाग पर किया गया, जिसको राज्य सांगठिनक कमेटी सदस्य कॉ.रचना अग्रवाल ने संबोधित किया। इसके अतिरिक्त कॉ.रूपेष्ठा जैन ने भी प्रदर्ष्ठान को संबोधित किया। भोपाल में प्रदर्ष्ठान स्थानीय जिन्सी चौराहे पर आयोजित किया गया जिसको राज्य सांगठिनक समिति सदस्य कॉ.जे.सी.बरई ने संबोधित किया। इसके अलावा जिला सांगठिनक सदस्य कॉ.जॉली सरकार ने भी प्रदर्ष्ठान को संबोधित किया। इंदौर में एक ज्ञापन रेल मंत्री के नाम एस.डी.एम.के माधयम से दिया गया।

बेरोजगारी, व्यापम महाघोटाला, बस्ती उजाड़ने एवं युवा समस्याओं के खिलाफ डी.वाई.ओ. का विरोध प्रदर्शन

भोपाल, 1 दिसम्बर: बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, अश्लीलता, अपसंस्कृति, व्यापम घोटाले आदि समस्याओं के खिलाफ प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए युवाओं ने ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सागर, गुना, अशाक नगर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए युवा शाहजानी पार्क पर एकत्रित हुए। बेरोजगारों को काम देना हो, जब तक काम नहीं न्यूनतम रु 3000 बेरोजगारी भत्ता देना होगा। व्यापम के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देना होगा। अश्लील फिल्म, अश्लील पोस्टरों पर रोक लगाओ, आदि गगन भेदी नारे लगाते हुए साथी नीलम पार्क के लिए रैली के रूप में निकले। नीलम पार्क पर रैली सभा में तब्दील हुई। यहाँ सभा को सम्बोधित करते हुए कर्नाटक से आए ऑल इण्डिया डी.वाई.ओ. के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बी. आर. मंजूनाथ ने कहा कि जहाँ एक तरफ देश में करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सरकार रोजगार देने की बजाए जिनके पास रोजगार है, उन्हें भी बेरोजगार बनाने की नीति अपना रही है। सरकारी अस्पतालों विद्यालयों महाविद्यालयों आदि में लाखों पद खाली पड़े हैं। पर सरकार उनकों भरने की बजाए या तो पदों को समाप्त कर रही है अथवा छ: महीने साल भार के लिए ठेके पर कम वेतन में नियुक्त कर रही है। आज जब युवाओं के नैतिक मान को उन्नत करने की जरूरत है ऐसे में सरकार शराब के नए ठेके खोलन कर व शराब बिक्री का समय बढ़ाकर युवाओं की नैतिक रीढ़ को तोड़ने की साजिश कर रही है। उन्होंने सभा में उपस्थित युवा साथियों को बधाई देते हुए कहा कि आप ही समाज की रोशनी की किरण हो जो इस घनघोर अंधेरे में युवाओं को संगठित करते हुए एक देशव्यापी जुझारू युवा आन्दोलन संगठित करेंगे।

सभा के मुख्य वक्ता सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) के राज्य सचिव कॉ. प्रताप सामल ने कहा कि तमाम सरकारें देश के चंद बड़े कॉरपोरेट घरानों के हित में नीतियाँ बना रही है। उन्हीं के फायदे के लिए जनता की महनत की कमाई से बने सार्वजनिक उपक्रमों व सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है। जिसके चलते लाखों लाख नौजवानों को अपने रोजगार से हाथ ध ोना पड़ रहा है। इतना ही नहीं म.प्र. में हुआ व्यापम महाघोटाला दर्शाता है कि किस तरह प्रेश के सत्ताध ारी व अफसरशाह उनके नाकाबिल बच्चों को अच्छी सरकारी नौकरी दिलाने के लिए प्रदेश के गरीब मध्यवर्गीय अभिभावकों व उनके काबिल प्रतिभावान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। उन्होंने सभी से सशक्त युवा आन्दोलन संगठित करने का आह्वान किय।

सभा के मुख्य अतिथि ट्रेड यूनियन काउंसिल के नेता व जाने माने साहित्यकार श्री जी.एस. आसीवाल ने कहा कि म.प्र. विभिन्न जिलों से आए नौजवानों ने उम्मीद बंधाई है कि आने वाली सदी समाजवाद की होगी। जहाँ हर छात्र को रोजगार शिक्षा व हर युवा को रोजगार मिल सकेगा। डी.वाई.ओ. की प्रदेश सह संयोजिका कॉ. प्रतिज्ञा मांझी ने भी अपनी बात रखी।

सभा की अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी कॉ. लोकेश शर्मा ने की। सभा में विभिन्न जिलों से आए साथियों ने जनगीत प्रस्तुत किए व आरोन की टीम ने एक नाटक का मंचन किया। आन्दोलन को और व्यापक तथा तीव्र बनाने के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समर्पण हुआ।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2012-2014
Posting at NDPSO on 7–8 and 22–23 Fortnightly , Date of Printing :21 January, 2015

छात्र आन्दोलन पर लाठी चार्ज

18 नवम्बर 2015, विभिन्न विश्वविद्यालयों से सैकड़ों छात्र यू.जी.सी. कार्यालय, नई दिल पर इकट्ठा हुए तथा 'ऑक्यूपाई यू.जी.सी.' के बैनर तले मानव संस्थान विकास मंत्रालय की तरफ जुलूस शुरू किया। 27 दिनों से ये छात्र दिन राज यू.जी.सी कार्यालय के सामने बैठे थे। प्रदर्शनस्थल पर जन सभाएं तथा विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम के बाद, जब यू.जी.सी. की तरफ से कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला तथा पुलिस का बर्बरतापूर्ण बर्ताव सहने के बाद आन्दोलनकारियों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ जाने का निर्णय लिया। ये छात्र नॉन नेट फेलोशिप को दोबारा शुरू करने, फेलोशिप को राज्य विश्वविद्यालयों तक पहुँचाने तथा फेलोशिप की मात्रा में वृद्धि करने की मांग कर रहे थे। यह मांग भी कर रहे थे कि फैलोशिप बिना शर्तों के हर एक छात्र को मिलनी चाहिए। जुलूस को एम.एच.आर.डी. से कुछ मीटर दूर ही रोक दिया गया। जहाँ एक जनसभा हुई। सभा को विभिन्न छात्र संगठनों जैसे आईसा, एआईएसएफ, केवाईएस, डीएसयू इत्यादि के नेताओं ने सम्बोधित किया। एआईडीएसओ की तरफ से संगठन के दिल्ली राज्य सचिव कॉ. प्रशांत कुमार ने भाषण दिया।

उन्होंने बताया कि हम साफ मांग करते हैं कि रिव्यू कमीटी को खत्म कर दिया जाए क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं रिव्यू कमीटी का मुख्य उद्देश्य जो मंत्रालय जो मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया है वह मापदण्ड निश्चित करना तथा गैर जनवादी मापदण्डों को तय कर छात्रों को बाहर निकालने को नया तरीका ढूँढ़ना है। हम यह भी महसूस करते हैं कि फण्ड कटौती शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने का बड़ा कदम है। विभिन्न पूँजीवादी-साम्राज्यवादी देशों की सरकारें दुनिया भर में बढ़ रहे बाजार संकट से बाहर आने व पूँजीपति घराने को अधिकतम मुनाफा पहुँचाने के क्रम में इसी दिसम्बर में नाईरोबी, केन्या में होने वाले विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन में शिक्षा को गैट्स के अंतर्गत लाने के प्रावधान पर अंतिम मोहर लगाने की ओर अग्रसर है। विश्व व्यापार संगठन में जनवादी शिक्षा को व्यापार की वस्तु बनाकर बेचने की तैयारियाँ चल रही हैं। उन्होंने आन्दोलनकारियों से इस आन्दोलन को व्यापक रूप से देश भर में फैलाने तथा शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण पर और भी सवाल उठाने की अपील की।

धर्मनिरपेक्षता के मायने को मनमाने ढंग से तोड़मरोड़ रहे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह

केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरह संसद में बोलते हुए 'धर्मनिरपेक्षता' शब्दा के मायने को मनमाने ढंग से विकृत किया है उसका तीव्र प्रतिवाद करते हुए एस.यू.सी.आई.(सी) के महामंत्री कॉमरेड प्रभाष घोष ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया:

आर.एस.एस.-बीजेपी एवं संघ परिवार के अन्यान्य संगठनों और शिवसेना के मतादर्श के साथ सामंजस्य रखने के उद्देश्य से केन्द्रीय गृहमंत्री ने 'धर्म निरपेक्षता' या 'सेक्युलरिज़्म' से सम्बंधित धारणा को जानबूझकर जिस तरह विकृत किया है। उसका हम तीव्र विरोध करते हैं। इतिहास का प्रत्येक छात्र जानता है कि पूँजीवाद के उत्थान के समय पश्चिम में नवजागरण काल के दौरान सामंती राजशाही और धर्माधारित प्राचीन सामंती सोच-विचार को दरकिनार करके संसदीय जनतंत्र के प्रादुभवि के साथ ही सेकुलरिज़्म की धारणा आई थी। जिसका मायने था किसी भी तरह की अतिप्राकृत सत्ता को स्वीकार न करना। एक असल सेकुलर राजसत्ता धर्म को उत्साहित या निरूत्साहित कतई नहीं करती है। धर्म को उसके असल स्थान पर रखती है। अर्थात् राजसत्ता के साथ धर्म का कोई सम्बंध नहीं रहेगा, इसे व्यक्ति के खुद के विश्वास के विषय के रूप में माना जाएगा। एक सेकुल राष्ट्र में, राजनीति में, शिक्षा में और सरकारी क्रियाकलापों में जिस तरह धर्म का स्थान नहीं रहता है। उसी तरह एक जनतांत्रिक समाज में आस्तिक और नास्तिक के अधिकार समान होते हैं। इसीलिए, इतिहास और विज्ञानसम्मत रूप से तथा सभी अर्थोंमें सेकुलरिज़्म शब्द का अर्थ 'धर्मनिरपेक्षता' को छोड़कर दूसरा और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन राजनाथ सिंह कह रहे हैं सेकुलरिज़्म का मायने 'सम्प्रदाय निरपेक्षता' या पंथ-निरपेक्षता होता है धर्मनिरपेक्षता नहीं।

गृहमंत्री के इस वक्तव्य से राजनीति, शिक्षा और सरकारी क्रियाकलापों में धर्म की भूमिका स्वीकृति पाएगी और इसके जरिए धर्ममुखी राजनीतिक पार्टियों और शक्तियों को राजनीति के मैदान में कूदने का उत्साह प्राप्त होगा। यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि कोई राष्ट्र यदि असल धर्मनिरपेक्षता का अनुसरण न करके किसी एक धर्म को उत्साह देता है तो वह धार्मिक राष्ट्र यदि सभी धर्मों को ही बढ़ावा दे तो वह बहुधर्मीय राष्ट्र में अधो पतित हो जाएगा। राजनाथ सिंह की बात के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का मतलब इसी जगह में ही पतित हो गया है। फिर राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं कि धर्मनिरपक्षता एक पश्चिमी धारणा है जो भारत के मामले में उपयोगी नहीं है यह भी गलत है। क्योंकि संसदीय गणतंत्र का गुणगान सभी बुर्जुआ मतावलम्बियों की तरह वे भी करते हैं, उस संसदीय गणतंत्र की धारणा का प्रादुभवि भी पश्चिमी देशों में ही हुआ था। धर्मनिरपेक्षता की इस तरह की विकृत व्याख्या देश के सामाजिक-राजनैतिक-सांस्कृतिक परिवेश को कलुषित किए बिना नहीं रह सकती है।

जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं के आधार पर, असल धर्मनिरपेक्षता की नीति के उपर जनआन्दोलन जैसे कि उठ खड़े न हो सकें, इसके लिए जनता को विभ्रांत करने का इस घृणित उद्देश्य से प्रेरित कुचेष्टा के खिलाफ असल धर्मनिरपेक्ष जनवादी पार्टियों और शक्तियों का तत्काल सक्रिय हो जाना जरूरी है।

इसके साथ ही जनता के प्रति हमारा आवेदन–लगातार बढ़ती जा रहे साम्प्रदायिक उन्माद के खिलाफ दृढ़तापूर्वक खड़े हो, गणतांत्रिक न्याय नीति और मूल्यबोध की पुन: प्रतिष्ठा के लिए सक्रिय होकर ऐसा एक परिवेश पैदा करिए जहाँ स्वतंत्र रूप से जन आन्दोलन उठ खड़ा हो सके।

फ्यूल सरचार्ज वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

रोहतक, (हरियाणा): 30-11-2015, गरीब किसानों और खेत-मजदूरों की मांगों पर विधान सभा का ध्यान आकर्षित करने और भाजपा सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज ऑल इण्डिया कृषक खेत मजदूर संगठन ने रोहतक शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। बिजली के दामों में भारी बढोतरी और बासमती धान की खरीद में किसानों की लूट के खिलाफ मुख्यमन्त्री के नाम उपायुक्त रोहतक को ज्ञापन दिया गया। प्रदेश भर से किसान व खेत मजदूर पहले छोटूराम पार्क में इकट्ठे हुए और अपनी माँगों के नारे लगाते हुए अपना माँग-पत्र देने के लिए लघु सचिवालय पहुँचे।

ज्ञापन में बिजली के रेट व फ्यूल सरचार्ज में की गई वृद्धि वापस लेने और घरेलू बिजली 2 रु. प्रति यूनिट करने, कम दाम पर बासमती धान बेचने पर मजबूर हुए किसानों को प्रति क्विंटल 800 रु. का मुआवजा देने, खराब हुई फसलों का मुआवजा देने, धान की खरीद में हुए घोटाले की जाँच कराने और खेत मजदूर के लिए पूरे साल काम का इन्तजाम करने की माँग की है। फसलों के लाभकारी दाम देने की माँग भी याद दिलाई।

विधान सभा सत्र के मौके पर इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई किसान नेता अनूप सिंह मातनहेल, जयकरण माण्डौठी, विजय कुमार, बाबूराम पबनावा, रामकुमार रिवाड़ी, बलबीर महेन्द्रगढ़, रोहताश और जिले सिंह भिवानी राजकुमार कुरुक्षेत्र ने की। अनूप सिह मातनहेल ने कहा जब तग हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, आन्दोलन को और भी विस्तार दिया जायेगा।